इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
एक नवरत्न कम्पनी
ENGINEERS INDIA LIMITED
(A Govt. of India Undertaking)
A Navratna Company
पंजीकृत कार्यालय : इंजीनियर्स इंडिया भवन, 1, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110 066 भारत
Regd. Office : Engineers India Bhawan, 1, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110 066 INDIA
ईमेल/e-mail: company.secretary@eil.co.in, दूरभाष /Phone: 011-26762855/2580
कंपनी सचिवालय/ **COMPANY SECRETARIAT**

सं.सचिव /No. Secy/906/9/10 09.06.2021

The BSE Limited **Phiroze Jeejeebhoy Towers** **Dalal Street, Fort** **Mumbai – 400 023**	**The National Stock Exchange of India Limited** **Exchange Plaza, 5th Floor** **Bandra Kurla Complex** **Bandra (East), Mumbai-400051**
Scrip Code-532178	**Symbol-ENGINERSIN**

विषय: समाचार पत्र विज्ञापन - वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट वित्तीय परिणाम

Sub: News paper Advertisement - Audited Financial Results for the FY 2020-21

प्रिय महोदय/महोदया,
Dear Sir/Madam,

In compliance of provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of news paper advertisement of Audited Financial Results for the FY 2020-21 published on 9th June, 2021.

कृप्या उपरोक्त को रिकॉर्ड मेंलें।
Kindly take the above on record.

भवदीय/Very truly yours,

नरेंद्र कुमार/ Narendra Kumar
अनुपालन अधिकारी/Compliance Officer

संलग्नक: यथोक्त/Encl: As above

परीक्षा के आधार पर प्रवेश मिलेगा, विश्वविद्यालय ने अपना ब्रोशर जारी किया

आईपीयू में 10 फीसदी बढ़ी सीटों के साथ दाखिले की प्रक्रिया शुरू

दाखिले की दौड़

40 हजार सीटों पर होगा दाखिला

15 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन

150 प्रोग्राम में दाखिला होगा

58 प्रोग्राम में कॉमन एंट्रेस टेस्ट

नई दिल्ली | प्रमुख संवाददाता

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में 10 फीसदी सीटों की बढ़ोतरी के साथ सत्र 2021-22 के लिए दाखिला प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई। 150 प्रोग्राम में लगभग 40 हजार सीटों पर दाखिले के लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.महेश वर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया से जुड़ा ब्रोशर जारी किया। छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ipu.ac.in पर ब्रोशर देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई है।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति ने कई नए कोर्स खोलने के साथ दो प्रोग्राम में पीएचडी शुरू करने की घोषणा की है। विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आटोमेशन एंड रोबोटिक्स के तहत पांच बीटेक प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। वहीं यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिजाइन एंड इनोवेशन के तहत बैचलर ऑफ डिजाइन कोर्स शुरू किया है। आईपीयू के कुलपति प्रो. महेश वर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही दाखिला होता है।

इस बार भी दाखिला एक स्वायत्त एजेंसी से होगा, जो दिल्ली सरकार के दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड सहित अन्य परीक्षाएं कराती हैं। ज्ञात हो कि विश्वविद्यालय ने विगत वर्ष भी इसी एजेंसी से परीक्षा आयोजित की थी। कुलपति ने यह भी कहा कि यदि सीटें बचती हैं तो मेरिट आधारित दाखिला के बारे में विचार किया जा सकता है। हालांकि इसकी संभावना कम है।

कई कोर्स में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं से दाखिला

विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि विगत वर्ष की भांति बीटेक, एमबीए, लॉ, मेडिकल, एमसीए, बीआर्क सहित अन्य कई कोर्स में दाखिला राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षा के तहत होगा। बीएससी नर्सिंग में नीट यूजी के तहत इस साल दाखिला होगा। 58 विषयों की प्रवेश परीक्षा कॉमन एंट्रेस टेस्ट के तहत होगी। यह परीक्षा अगस्त या सितंबर में होने की संभावना है।

परास्नातक और पीएचडी में भी नए कोर्स शुरू होंगे

विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के तहत परास्नातक स्तर पर एम आर्क और एम प्लान शुरू करने की घोषणा की है, जबकि यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बेसिक एंड एप्लाइड साइंसेज के तहत एमएससी इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स संचालित करने की घोषणा की है। साथ ही विश्वविद्यालय ने इकोनॉमिक्स एंड आर्किटेक्चर में पीएचडी प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है।

सूरजमल विहार कैंपस में पांच नए कोर्स शुरू हो रहे

1. बीटेक इन आर्टिफिशिएल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस
2. बीटेक इन आर्टिफिशिएल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग
3. बीटेक इन इंडस्ट्रियल इंटरनेट थिंग्स
4. बीटेक इन आटोमेशन एंड रोबोटिक्स
5. बैचलर ऑफ डिजाइन

बीपीएससी में 16 छात्र चयनित हुए

नई दिल्ली (व.सं.)। जामिया की आवासीय कोचिंग अकादमी (आरसीए) के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन दोहराया है। इस बार आरसीए के 16 छात्रों का चयन बिहार प्रशासनिक सेवा में हुआ है। इन सभी ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 64वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) पास की है। चयनित छात्रों को बिहार में एसडीएम, डीएसपी, राजस्व अधिकारी, वाणिज्यिक कर अधिकारी, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग आदि के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

14 जून के बाद यूपी जाएंगी बसें

नई दिल्ली (का.सं.)। राजधानी में अनलॉक के बाद भी यूपी और उत्तराखंड रोडवेज बसों का परिचालन शुरू नहीं हो सका है। दिल्ली से यूपी और उत्तराखंड के लिए सफर के लिए यात्रियों को अभी इंतजार करना होगा। यहां तक की हिमाचल प्रदेश के लिए भी अभी बसें नहीं मिल रही हैं। इन राज्यों के लिए 14 जून के बाद बसों के परिचालन को लेकर अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं। कश्मीरी गेट व आनंद विहार बस अड्डा प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार अभी बसों का परिचालन बंद है। यूपी की बसें अभी कौशांबी तक आ रही हैं।

रेस्टोरेंट बंद कर शुरू किया ढ़ाबा

नई दिल्ली (वा.सं.)। मालवीय नगर में फूड स्टॉल बाबा का ढ़ाबा चलाने वाले बुजुर्ग कांता प्रसाद ने नुकसान के बाद रेस्टोरेंट बंद कर दिया है।

रेस्टोरेंट बंद करने के बाद एक बार फिर कांता प्रसाद ने अपना फूड स्टॉल बाबा का ढ़ाबा शुरू कर दिया है। जहां से वह प्रसिद्ध हुए थे। हालांकि लॉकडाउन और कोरोना के चलते बाबा का ढाबा पर भी आमदनी कम है, जिसके चलते एक बार फिर आर्थिक संकट में फंस गए हैं। बीते साल कांता प्रसाद का वीडियो वायरल होने के बाद देश-विदेश के लोगों ने मदद की और उन्होंने मालवीय नगर में ही रेस्टोरेंट खोला था।

तीन माह बढ़ाया गया कार्यकाल

नई दिल्ली (प्र.सं.)। डीयू ने कोविड-19 से उपजी स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा पूर्ण व आंशिक वित्त पोषित कॉलेजों की 28 गवर्निंग बॉडी के सदस्यों का कार्यकाल तीन माह के लिए बढ़ा दिया है।

ज्ञात हो कि पूर्व में आप के शिक्षक संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल इस बाबत डीयू से मिला था।

गर्मी ने छुड़ाया पसीना, पारा 41 के पार

मौसम का मिजाज

नई दिल्ली | प्रमुख संवाददाता

राजस्थान और हरियाणा की ओर से आने वाली पश्चिमी हवाओं के चलते दिल्ली के तापमान में इजाफा हो रहा है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार को पारा 41 डिग्री के पार हो सकता है। हालांकि, इसके बाद से तापमान में गिरावट का क्रम शुरू हो जाएगा। पूरब से आने वाली हवाओं के चलते हुई बूंदाबांदी से अगले सोमवार तक अधिकतम तापमान गिरकर 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में मंगलवार की सुबह से तेज धूप का लोगों को सामना करना पड़ा। दिन चढ़ने के साथ ही धूप और गर्म हो गई। इससे घर से बाहर काम से निकलने वालों को परेशानी झेलनी पड़ी। खासतौर पर पश्चिम से आ रही गरम हवाओं के चलते दिन के समय लोगों को लू जैसा अहसास भी हुआ। मौसम विभाग के अनुसार ये हवाएं एकदम शुष्क हैं और इनकी रफ्तार भी तेज है। इससे गर्मी में तेजी से इजाफा हुआ है। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केन्द्र में दिन का अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से एक डिग्री ज्यादा है। जबकि, न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो कि सामान्य से एक डिग्री ज्यादा है। प्रादेशिक मौसम पूर्वानुमान केन्द्र के प्रमुख डॉ. कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली का आसमान फिलहाल पूरी तरह से साफ है। बादल नहीं होने से सूरज की तेज धूप आ रही है। जबकि, पश्चिम से शुष्क हवाएं आ रही हैं। इसके चलते गर्मी बढ़ी है। बुधवार को भी साफ आसमान और तेज धूप के चलते तापमान में इजाफा होगा। इस दौरान हवा की रफ्तार भी 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है।

12 जून से दिल्ली में हल्की बारिश होने की जताई जा रही संभावना

28.6 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान, यह सामान्य से एक डिग्री ज्यादा है

पूर्वी हवाओं से मिलेगी राहत

बंगाल की खाड़ी में एक कम हवा का दबाव क्षेत्र बन रहा है। दिल्ली में भी हवा के रुख में बदलाव होगा और पूर्वी हवाएं अपने साथ नमी लेकर आएंगी। इसके चलते 12, 13 और 14 तारीख को दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बरसात भी हो सकती है। इससे 14 जून तक अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी।

राजस्थानी धूल से खराब हुई राजधानी की हवा

राजस्थान की तरफ से आने वाली धूल भरी हवाओं के चलते दिल्ली की हवा फिर से खराब हो गई। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, मंगलवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के अंक के पार हो गया। सफर का अनुमान है कि अगले दो-तीन दिनों के बीच वायु गुणवत्ता का स्तर इसके आसपास ही बना रहेगा। सीपीसीबी के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 205 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। इससे पूर्व 23 मई को भी पूरे वातावरण में धूल की एक परत छा गई थी।

अगले हफ्ते मिल सकती है राहत

नई दिल्ली (प्र.सं.)। दिल्ली में तेज धूप के चलते बुधवार को पारा 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। हालांकि, इसके बाद से तापमान में गिरावट का क्रम शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते होने वाली बूंदाबांदी से अगले सोमवार तक अधिकतम तापमान गिरकर 34 डिग्री तक पहुंच सकता है।

35 किमी रफ्तार से चलेगी हवा

नई दिल्ली (प्र.सं.)। मौसम विभाग का अनुमान है बुधवार के बाद से तापमान में गिरावट का दौर जारी होगा। विभाग के अनुसार इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण राजधानी दिल्ली में हवा की रफ्तार 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इससे आने वाले हफ्ते में दिल्ली वालों को तपती गर्मी से थोड़े समय के लिए राहत मिलेगी।

वर्षा जल संचयन पर 6 माह की छूट

नई दिल्ली (प्र.सं.)। कोरोना काल के चलते दिल्ली जल बोर्ड ने वर्षा जल संचयन सिस्टम नहीं लगाने पर लगाए जाने वाले जुर्माने पर छह महीने की छूट दी है। नए कनेक्शन पर इसकी बाध्यता पर भी छह माह की राहत दी गई है।

जल बोर्ड ने 100 वर्ग मीटर से ज्यादा के प्लाट पर बने मकानों के लिए वर्षा जल संचयन सिस्टम लगाने को अनिवार्य किया था। ऐसा नहीं करने वालों पर लेवी लगाए जाने को कहा गया था। लेकिन कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए जल बोर्ड ने 30 सितंबर तक के लिए टाल दिया है। जबकि, नए कनेक्शन के लिए इसकी अनिवार्यता भी छह महीने के लिए समाप्त कर दी गई है।

सूर्य ग्रहण के बारे में जानेंगे छात्र

नई दिल्ली (का.सं.)। सूर्य ग्रहण को लेकर नेहरू तारामंडल द्वारा छात्रों के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें छात्रों को सूर्य और ग्रहण के बारे में जानकारी दी जाएगी।

नेहरू तारामंडल के अनुसार दस जून को आंशिक तौर पर ग्रहण एक बजकर 42 मिनट पर देखा जाएगा। फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण तीन बजकर 19 मिनट पर और अधिकतम सूर्य ग्रहण की स्थिति चार बजकर 11 मिनट के करीब देखने को मिलेगा। यह सूर्य ग्रहण पांच घंटे तक चलेगा। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में वलयाकार सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा। रूस, ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा दिखेगा।

इकबाल सिंह, श्याम सुंदर, मुकेश ने नामांकन किया

नई दिल्ली | वरिष्ठ संवाददाता

महापौर चुनाव

- तीनों नगर निगमों में भाजपा का बहुमत होने के कारण इनका चुना जाना तय माना जा रहा
- उत्तरी, पूर्वी और दक्षिण निगम में महापौर पद के लिए भरे गए नामांकन पत्र

राजधानी के तीनों नगर निगमों में महापौर पद के लिए मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल कर दिए गए। तीनों निगमों में भाजपा का बहुमत होने के चलते उत्तरी निगम से राजा इकबाल सिंह, पूर्वी निगम के श्याम सुंदर अग्रवाल और दक्षिण निगम से मुकेश सूर्यान का महापौर होना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही उप-महापौर, नेता सदन और स्थायी समिति अध्यक्ष के लिए भी शाम तक एक-एक नामांकन पत्र दाखिल हुए। तीनों निगम सचिव का कहना है कि महापौर, उप-महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव 16 जून 2021 को होने हैं।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय सिविक सेंटर में मंगलवार दोपहर बाद महापौर सहित अन्य पदों के लिए नामांकन पत्र भरे जाने शुरू हुए। महापौर पद के लिए पार्षद राजा इकबाल सिंह ने, जबकि अर्चना दलीप सिंह ने उप-महापौर के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। राजा इकबाल सिंह वर्तमान में सिविल लाइंस जोन के चेयरमैन हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में महापौर पद के लिए श्याम सुंदर अग्रवाल ने और उप-महापौर के लिए किरण वैद्य ने अपना नामांकन पत्र भरा। इससे पहले श्याम सुंदर अग्रवाल शाहदरा दक्षिण जोन के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं।

दक्षिण दिल्ली नगर निगम में महापौर पद के लिए मुकेश सूर्यान और उप-महापौर पद के लिए पवन शर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल किया।

नामांकन पत्र दाखिल किए

तीनों निगमों के निगम सचिव ने बताया कि महापौर और उप-महापौर पद के नामांकन पत्र दाखिल होने के साथ ही नेता सदन और स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए भी नामांकन पत्र भरे गए हैं। इनमें उत्तरी निगम से नेता सदन के लिए छैल बिहारी गोस्वामी, स्थायी समिति अध्यक्ष के लिए जोगीराम जैन और उपाध्यक्ष के लिए विजय कुमार भगत ने अपना-अपना नामांकन पत्र भरा है।

स्थायी समिति के बाद चेयरमैन पद के चुनाव होंगे

पूर्वी निगम में नेता सदन के लिए सत्यपाल सिंह, स्थायी समिति अध्यक्ष के लिए वीर सिंह पवार और उपाध्यक्ष पद के लिए दीपक मल्होत्रा ने अपना पर्चा दाखिल किया। दक्षिण दिल्ली निगम में नेता सदन के लिए इंद्रजीत सहरावत, स्थायी समिति अध्यक्ष के लिए कर्नल बीके ओबराय और उपाध्यक्ष पद के लिए पूनम भाटी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। महापौर, उप-महापौर सहित स्थायी समिति के चुनाव होने के बाद तीनों नगर निगमों के 12 जोन के लिए चेयरमैन पद के चुनाव होंगे।

वित्तीय आवेदन में मदद करेंगे मोबाइल सहायक

नई दिल्ली | वरिष्ठ संवाददाता

50 रुपये होगा शुल्क, 1076 पर कॉल करके मोबाइल सहायक बुला सकेंगे

05 हजार रुपये की वित्तीय मदद की घोषणा की है दिल्ली सरकार ने

वित्तीय मदद पाने के लिए चालकों को आवेदन में आ रही दिक्कत दूर करने के लिए परिवहन विभाग ने मोबाइल सहायक टीम तैनात की है। चालकों को इसके लिए 1076 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मदद मांगनी होगी। उसके बाद मोबाइल सहायक उनके पास पहुंचकर उनकी आवेदन में मदद करेंगे। हालांकि इसके लिए चालक को 50 रुपये का शुल्क देना होगा।

दरअसल दिल्ली सरकार को शिकायतें मिल रही थी, कि बहुत से चालकों का आवेदन नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसी भी शिकायतें थीं, कि आवेदन के बाद भी उनका पैसा बैंक में नहीं आया है। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, ऐसी शिकायतें इसलिए क्योंकि लोग आवेदन में कुछ न कुछ कमी छोड़ देते हैं। इसलिए अब आवेदन के लिए मोबाइल सहायक की मदद ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें 1076 पर कॉल करना करना होगा।

परिवहन विभाग के मुताबिक, बीते साल जिन लोगों का पैसा बैंक में आ गया था उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। उनका पैसा दोबारा उसी बैंक खाते में पहुंच जाएगा। बताते चलें कि दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के चलते, ऑटो, बस, ई-रिक्शा, मैक्सी कैब समेत अन्य चालक जिनके पास पीएसबी बैज व लाइसेंस है। दिल्ली सरकार के मुताबिक, दिल्ली में ऐसे 1.56 लाख से अधिक चालक है।

लाडली योजना के लंबित मामलों को जल्द निपटाएं

नई दिल्ली | वरिष्ठ संवाददाता

निर्देश

- महिला एवं बाल विकास मंत्री का अधिकारियों को निर्देश
- लाड़ली योजना के लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने को कहा

लॉकडाउन के चलते लाडली की लंबित योजनाओं के तेजी से निपटारे के लिए अब विभागीय कर्मचारी घर-घर जाकर दस्तावेज पूरा करेंगे। मंगलवार को समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की अध्यक्षता में दोनों विभागों के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में अधिकारियों को लाडली योजना के साथ वित्तीय सहायता और पेंशन योजनाओं के सभी लंबित मामलों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए।

राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि सभी वित्तीय सहायता से जुड़ी योजनाओं के आवेदनों की बारीकी से समीक्षा की जाए। लंबित मामलों को तुरंत खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि 'दिल्ली लाडली' योजना के अंतर्गत जो परिवार योजना के तहत परिपक्वता लाभ लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, अधिकारी उनके घर-घर जाकर बारीकी से जांच-पड़ताल कर मामले का निस्तारण करें। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत अखबारों में बार-बार सार्वजनिक नोटिस देने के बाद भी लाभार्थी योजना का मैच्योरिटी लाभ लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।

31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों का सारांश

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	एकल					समेकित				
		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
		31-मार्च-21 (लेखापरीक्षित)	31-दिसम्बर-20 (गैर-लेखापरीक्षित)	31-मार्च-20 (लेखापरीक्षित)	31-मार्च-21 (लेखापरीक्षित)	31-मार्च-20 (लेखापरीक्षित)	31-मार्च-21 (लेखापरीक्षित)	31-दिसम्बर-20 (गैर-लेखापरीक्षित)	31-मार्च-20 (लेखापरीक्षित)	31-मार्च-21 (लेखापरीक्षित)	31-मार्च-20 (लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से राजस्व	1,11,670.64	83,672.95	85,381.04	3,10,468.78	3,20,305.08	1,13,190.42	84,548.94	86,438.26	3,14,416.94	3,23,653.63
2	अन्य आय	4,399.30	4,797.18	6,850.64	19,487.87	25,803.46	3,985.05	4,880.58	6,635.34	18,877.69	25,553.60
3	कुल आय	1,16,069.94	88,470.13	92,231.68	3,29,956.65	3,46,108.54	1,17,175.47	89,429.52	93,073.60	3,33,294.63	3,49,207.23
4	अवधि के लिए निवल लाभ (कर, अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों से पूर्व)	19,857.62	11,755.31	17,221.05	50,553.25	67,550.90	20,136.06	12,039.55	17,224.40	51,128.64	68,301.91
5	अवधि के लिए कर पूर्व निवल लाभ (अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों के बाद)	4,361.14	11,755.31	17,221.05	35,056.77	67,550.90	4,639.58	12,039.55	17,224.40	35,632.16	68,301.91
6	अवधि के लिए कर पश्चात निवल लाभ (अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों के बाद)	3,054.10	8,819.87	12,972.46	25,949.73	43,024.37	3,141.08	9,031.86	12,897.68	26,145.56	43,385.96
7	संयुक्त उद्यम इकाईयों में लाभ/(हानि) का शेयर	-	-	-	-	-	(648.28)	(224.57)	(929.10)	(1,254.60)	(1,004.08)
8	अवधि के लिए लाभ	3,054.10	8,819.87	12,972.46	25,949.73	43,024.37	2,492.80	8,807.29	11,968.58	24,890.96	42,381.88
9	अवधि के लिए कुल व्यापक आय {अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल}	4,118.38	8,459.64	10,846.23	25,865.54	39,966.64	3,553.45	8,452.03	9,794.40	24,817.95	39,282.42
10	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 5/-)	28,102.13	31,595.58	31,595.58	28,102.13	31,595.58	28,102.13	31,595.58	31,595.58	28,102.13	31,595.58
11	अन्य इक्विटी				1,41,998.73	2,02,950.16				1,46,968.63	2,09,006.31
12	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (₹ 5/- प्रत्येक के ₹ प्रति शेयर)										
	i) अतिविशिष्ट मदों से पूर्व मूल एवं तनुकृत ईपीएस ₹ में	0.54	1.39	2.05	4.16	6.81	0.45	1.39	1.90	3.99	6.71
	ii) अतिविशिष्ट मदों के पश्चात मूल एवं तनुकृत ईपीएस ₹ में	0.54	1.39	2.05	4.16	6.81	0.45	1.39	1.90	3.99	6.71

टिप्पणी :

1. लेखापरीक्षा समिति द्वारा उपरोक्त परिणामों की समीक्षा की गई है तथा निदेशक मंडल द्वारा 8 जून, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया है।
2. लेखापरीक्षित खाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा समीक्षा के अधीन हैं।
3. ये वित्तीय परिणाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और संबंधित प्रासंगिक संशोधन नियमों के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।
4. निदेशक मंडल ने वर्ष के दौरान भुगतान किए गए ₹ 1.40 प्रति शेयर (अंकित मूल्य ₹ 5.00 प्रति शेयर) के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त ₹ 0.60 प्रति शेयर (अंकित मूल्य ₹ 5.00 प्रति शेयर) के अंतिम लाभांश की अनुशंसा की है। अंतिम लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।
5. पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
6. उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता एवं अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है। यह कम्पनी की वेबसाइट www.engineersindia.com पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
हस्ता./-
(सुनील भाटिया)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 08259936

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 08 जून, 2021

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)
उत्कृष्टता का आधार – हमारे कर्मी

पंजीकृत कार्यालयः इंजीनियर्स इंडिया भवन, 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066; फोनः 011–26762121 | ई–मेलः eil.mktg@eil.co.in
वेबसाइटः www.engineersindia.com | सीआईएनः L74899DL1965GOI004352

Follow us :
/EngineersIND @EngineersIND
/company/engineers-india-limited

EC urges govt to expedite pending electoral reforms

Deeksha Bhardwaj
letters@hindustantimes.com

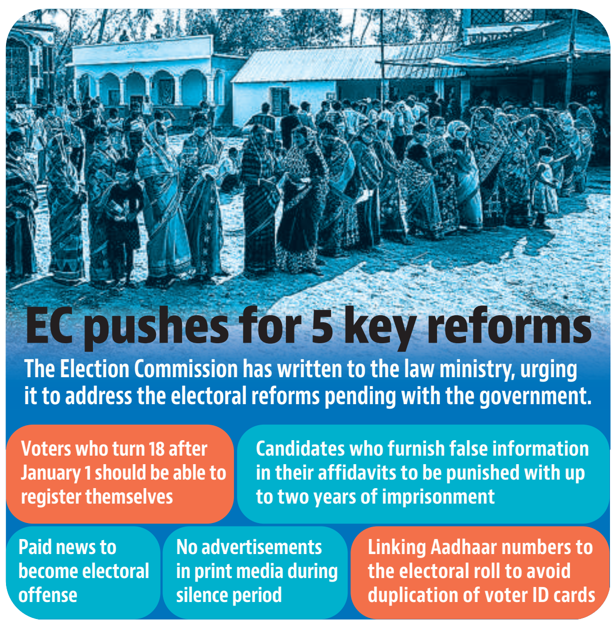

NEW DELHI: The Election Commission of India is pushing for at least five key electoral reforms including making paid news an electoral offence, linking Aadhaar numbers to the electoral roll , and increasing the punishment for filing a false affidavit (to two years of imprisonment), and has written to the government in this regard, officials familiar with the matter said on condition of anonymity.

ECI has written to the law ministry urging it to "expeditiously" address electoral reforms that are pending with the government, which also includes multiple registration dates in a year for new voters, the official added. There are nearly 40 proposals pending with the ministry.

Elections in the states of Goa, Manipur, Uttarakhand, Punjab and Uttar Pradesh are due next year.

ECI has been considering a wide range of electoral reforms to usher in digitisation, removing duplication of voters and enabling remote voting for non-resident Indians (NRIs), even migrant workers within the country. "The commission on May 17, sent a reminder to the law minister Ravi Shankar Prasad to revisit the reforms," the official cited in the first instance said.

Political leaders and experts argue that while some of the reforms mentioned are good, the focus should instead be on countering hate speech and bringing transparency to the electoral bond process. ECI, however, has highlighted these five reforms in its letter.

One, it has proposed that the voters who turn 18 should be able to register more than just once in year. At present, only those who turn 18 as of January 1 are eligible to register as voters. "This causes many people to lose out an entire year where they do not get to vote," the official said. "The Commission has proposed four dates, January 1, April 1, September 1 and December 1 as prospective registration dates instead."

A second EC official familiar with the matter said that the first time a recommendation on multiple dates of registration was made was in the 1970s (when the voting age was 21).

Two, ECI wants to get tough on false affidavits. At present, candidates who furnish false information can be punished with up to six months of imprisonment. The Commission has suggested increasing this to two years.

"The present jail term does not result in the disqualification of the candidate," the first official said. "An increased term can lead to the candidate being disqualified for six years." A historic Supreme Court judgement in 2013 ruled that a lawmaker sentenced to prison for at least two years will lose membership of the house, be disqualified for the period of the sentence, and for six years after that period as well.

Three, ECI wants to make paid news an electoral offense.

Four, it has also suggested that advertisements in print media (newspapers, journals) be barred during the silent period, wherein candidates are not allowed to campaign.

Five, ECI wants to link Aadhaar data to the electoral roll , part of its plan to eliminate duplication of voter ID cards. "It will also ensure that when a person moves to a different state, their voter ID card does not have to be issued from scratch. It can just be transferred," the first official said.

All the proposed reforms will require amendments to the Representation of People's Act, 1951.

BJP MP Rakesh Sinha said that such reforms are essential to strengthen Indian democracy. "There is need to curb fake and bogus voters and the best way is to link voters with their Aadhaar card," he said.

"This will end the prevailing ailment. Anyone contesting election has moral and constitutional responsibilities to reveal required information but deliberate anomalies are blot on democracy. Such representatives cannot be truthful to their constitutional obligations. Therefore, the move of the EC is just ."

Congress MP Manish Tewari, however, argued that the Commission was paying "lip service" and should instead focus on regaining its credibility.. "The EC has absolutely lost the credibility and the confidence of the Indian people," Tewari said. "It is seen as another arm of the government and before it starts pontificating about reforms, it must work to regain its credibility."

Tewari added that ECI needs to be cognizant that the Madras High Court went to the extent of observing that its officials should be tried for murder because of the "cavalier nature" of formulating the election schedule even as the second wave of the pandemic hit. "It has no credibility for the simple reason that any autonomous institution needs to speak truth to power and only then can they inspire confidence. These reforms are nothing but lip service to try and regain its demolished credibility."

RJD MP Manoj Jha said that the Commission was going for low hanging fruit. "The most important electoral reform needed as of now is total transparency in electoral bonds," he said. "That should be a priority area for the EC."

He added that the Commission has also not done anything substantial to counter hate speech and polarizing speeches.

But former CEC SY Queraishi said that these are long pending reforms. "These have been around for a long time," he said. "I would be happy if a sixth is added that appointment of election commissioners is by a collegium and elevation to CEC is by seniority so that the two (other election) commissioners do not feel that they are on probation."

According to a former chief election commissioner who did not wish to be named, every CEC tries to push through the reforms, but without much success. "What is more important that the Commission remain autonomous," the former CEC said.

"These reforms are neither major nor significant. Linking of voter id numbers with Aadhaar is particularly dangerous and was even quashed by the Supreme Court. Increasing the punishment is okay but one needs to see how many convictions for false affidavits have been made so far," Jagdeep Chhokar of Association for Democratic Reforms, said.

"Paid news will be impossible to define and even harder to prove. What is needed is laws that are implementable," he added.

Suvendu Adhikari

SUVENDU MEETS SHAH, NADDA TO DISCUSS POLL VIOLENCE IN STATE

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

KOLKATA: Bharatiya Janata Party (BJP) legislator and leader of opposition in West Bengal assembly, Suvendu Adhikari, on Tuesday met Union home minister Amit Shah and party chief JP Nadda in Delhi to discuss post-poll violence in the eastern state. "I personally feel that the situation in Bengal is much worse than what is required to enforce Article 356. However, our party has not taken a formal stand on this issue yet. Wait and see," said Adhikari, who is slated to meet Prime Minister Narendra Modi on Wednesday.

Under Article 356 of the Constitution of India, in the event that a state government is unable to function according to Constitutional provisions, the Union government can take direct control of the state machinery. The TMC claimed that Adhikari's meeting with the Union minister and top BJP leaders in Delhi was to save himself from CBI prosecution in the Narada sting tapes case. "Bogey of President's Rule being raised in Bengal even by Tarpaulin Thief to divert attention. HIS MASTER'S VOICE !" TMC leader Sukhendu Sekhar Roy tweeted.

TMC turncoat skips BJP meeting

Meanwhile, BJP leader Rajib Banerjee on Tuesday skipped a crucial meeting of office bearers called by state president Dilip Ghosh, triggering speculations about rising dissent in the party. Taking to social media, Banerjee, who quit the TMC to join the BJP but lost the polls from Domjur seat, said the "people will not take kindly to threats of President's rule" against a government elected with a huge mandate.

Rajasthan cabinet shuffle likely in July to pacify disgruntled leaders

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

JAIPUR: A much-awaited cabinet reshuffle in Rajasthan is likely to take place next month as the Congress leadership has begun the exercise amid rising dissent in the state unit, a senior party leader familiar with the development said on Tuesday.

At present, Rajasthan has 21 ministers, including the chief minister. The state with 200 assembly constituencies can appoint a maximum of 30 ministers. On Tuesday, Hindustan Times reported that last year's crisis in the state that the Congress papered over by setting up a committee to address the issues raised by then deputy chief minister Sachin Pilot against chief minister Ashok Gehlot have resurfaced with the former expressing his displeasure at the lack of action.

Pilot told Hindustan Times that the Congress high command had failed to deliver on the promises that were made to him when he along with 18 legislators returned to the party after a month-long drama.

CURRENTLY, THE STATE HAS 21 MINISTERS, INCLUDING THE CHIEF MINISTER. IT CAN APPOINT A MAXIMUM OF 30 MINISTERS

A senior leader familiar with the development said the leadership has initiated the process of reshuffling and efforts are being made to pacify the disgruntled faction by inducting some new faces.

The leader added that while the issue could be resolved in a day or two, demanding appointments on the basis of faction wasn't justified and was also a cause of concern for the party.

What the party high command suggested was appointing and proposing names on the basis of merit after discussions, the leader said. "All efforts are at present focused on building consensus among the state leaders," he said.

Everyone in the Congress, the leader said, understood that any further delay would lead to more damage to the party and demoralise workers and MLAs, be it via political appointment or cabinet reshuffle.

"The party after the political crisis last year had included names from the Pilot faction in the state executive. Similarly, three to four ministers as suggested by him (Pilot) would be finding space in the cabinet. It is expected that after Rahul Gandhi's appointment as the party chief, the cabinet expansion would be done in July," the leader said.

ANUP CHANDRA PANDEY NAMED ELECTION COMMISSIONER

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Former Uttar Pradesh chief secretary Anup Chandra Pandey was on Tuesday appointed as the new election commissioner by the President, filing the third post that fell vacant in April following the retirement of former chief election commissioner Sunil Arora.

"In pursuance of clause (2) of article 324 of the Constitution, the President is pleased to appoint Shri Anup Chandra Pandey, IAS (Retd.) (UP: 1984) as the Election Commissioner with effect from the date he assumes the office," the gazette notification released late Tuesday evening said.

The 1984-batch IAS officer holds a doctorate in ancient history and served as the Uttar Pradesh chief secretary from September 2017 to August 2019. The former bureaucrat has also served in the central government.

House panel meetings to resume from June 21

Saubhadra Chatterji
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: After a gap of more than two months, Indian parliamentary committees will resume their meeting from June 21, authorities involved in the planning said on Tuesday.

"The chairpersons of the standing committees have been informed that they can resume panel meetings from June 21," said a senior MP who heads a panel.

Officials maintained that June 21 was chosen keeping in mind the ongoing lockdown in some states. Authorities expect that by June 21, the remaining restrictions will be lifted amid an improving Covid situation in large parts of the country.

On June 21, the government will also switch to the centralised vaccine programme, in which the Union government will provide free vaccine to the states. Prime Minister Narendra Modi announced on Monday that the states will not have to pay for the vaccines and all adults can receive free vaccines organised by the Centre.

When the second wave of Covid hit India in March, leaving the Capital and large parts of the country reeling, many House committees had to cancel their meetings and no new meeting were planned.

Indian Parliament could work for only 34 days since the pandemic hit Indian shores in March 2020. The entire winter session of 2020 had to be cancelled while last three other sessions were cut short.

The Labour panel, led by Biju Janata Dal member Bhartruhari Mahtab, had planned to meet on April 23 on cotton plantations and scheduled a study tour in April. "We had to cancel both. In my panel, at least 15-16 members are in the NCR [national capital region] or UP and can travel by road to attend any panel meetings. But some of those members were reluctant to come for meetings," said Mahtab.

The panel will now meet on June 23.

Convergence Energy Services Limited
A wholly owned subsidiary of EESL
2nd Floor, NFL Building, Core-III, SCOPE Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003

RECRUITMENT NOTICE

CESL, a wholly owned subsidiary of Energy Efficiency Services Limited (EESL), which is a JV of PSUs under Ministry of Power, Government of India invites applications for the position of **Manager (Commercial & BD) (Regular) and Manager (Project Monitoring Cell) (Regular).**

Details w.r.t eligibility criteria, selection mode, online application etc. shall be made available on CESL website under CESL HR Career Section from **07/06/2021.**
www.convergence.co.in

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY LIMITED
(A Govt. of West Bengal Enterprise)
Regd. Office : Vidyut Bhavan, Block-DJ, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata - 700 091
CIN : U40109WB2007SGC113473, cecorpmont@gmail.com, www.wbsedcl.in
WBSEDCL

Tenders are invited by the **Chief Engineer, Procurement & Contracts Department, WBSEDCL,** Vidyut Bhavan (4th Floor), Block-DJ, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-91 through e-Tendering from genuine manufacturers only for manufacture, testing, supply and delivery of the following items: **3 Ph 4 wire, CT/PT operated, tri-vector 0.5s class, energy meters for 11 kV feeder metering** through **Tender Notice No.:** P-04/2021-22/PC-I. **Quantity (Nos.):** 1000; **Estimated Value (approx.):** Rs. 85.16 Lakh; **Last date of submission of Tender:** 14.07.2021. Tenders are to be submitted online through **www.wbtenders.gov.in**. For further details, visit **www.wbsedcl.in** and the above-mentioned office [**Ph. No.:** (033) 23197563]. ICA- T6519(2)/2021

SANJAY GANDHI POSTGRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
Raebareli Road, Lucknow, 226014 (UP)

Cafeteria tender from reputed firms for a period of 3 years.
The detail terms and conditions are available on our website (www.sgpgi.ac.in) The offer will only be accepted through GEM Portal with terms and condition as mention in tender document. Last date and time of submission of tender document is **18th June 2021 at 03:00PM.**
The Director reserves the right to accept or reject any offer partially or fully without assigning any reason.

ADVT.No.: I/06/Cafeteria/2021-22
Dr. R.P. Singh
Chief Medical Social Service Officer
S.G.P.G.I.M.S. Lucknow

एन सी एल NCL
Northern Coalfields Limited
(A Miniratna Company)
(A Subsidiary of Coal India Limited)

Tender Notice

"All the tenders issued by CIL and its Subsidiaries for procurement of Goods, works and Services are available on website of Coal India Limited **www.coalindia.in/** respective subsidiary Company, CIL e-procurement portal **https://coalindiatenders.nic.in** & central public procurement portal **https://eprocure.gov.in**. In addition, procurement is also done through GeM Portal **https://gem.gov.in** ." R-13

Rail Land Development Authority
(A Statutory Authority under Ministry of Railways, Government of India)
Unit No. 702-B , 7th Floor, Konnectus Tower-II DMRC Building,
Ajmeri Gate, Delhi-110002 Phone: + 91-11-23232854, Fax: +91-11-23232835

REQUEST FOR PROPOSAL THROUGH E-TENDER
(RFP Notice No. RLDA/RFP/CD-16 of 2021)

GRANT OF LEASE FOR REDEVELOPMENT OF 2.18 HA OF BOULEVARD ROAD RAILWAY COLONY, DELHI FOR 99 YEARS

Land	Area of the Site	FSI	Bid Security	Reserve Price
Boulevard Road Railway Colony, New Delhi	21800 Sqm.	Maximum Permissible FSI on the subject site is 0.75 on Gross Area of Plot	Rs. 1.20 Crore	Rs. 393 Crore

ONLINE PRE-BID MEETING ON WEBEX: 18th JUNE, 2021 AT 11:30 HRS.
(For registration for Online Pre-Bid Meeting – Interested Bidders please mail at gmbd@rlda.railnet.gov.in latest by 17.06.2021 upto 17:00 hrs.)
Last Date of Submission of E-bid Online: 23.07.2021 UPTO 15:00 HRS
For further details of the project, please visit our website www.rlda.indianrailways.gov.in or on e-procurement portal www.tenderwizard.in/RLDA under the heading **'e-tender'**
For any clarifications, may please contact:-

Dy. General Manager/Project-I	General Manager/Project-4	Consultant/RLDA	For E-bid Queries- Mr. Suraj
M: 97176 31068	M: 97737 66004	Mr. Abhilesh Babel, M: 96500 24555	M: 95996 53865
dgmne@rlda.railnet.gov.in	gmbd@rlda.railnet.gov.in	infra.advisory@feedbackinfra.com	suraj@etenderwizard.com

Note:- Any Corrigendum or Addendum shall be published only on RLDA's Website. **DGM/Tender, (M) 7703918078**

भारत सरकार Government of India
अंतरिक्ष विभाग Department of Space
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन Indian Space Research Organisation
अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SPACE APPLICATIONS CENTRE
अहमदाबाद Ahmedabad 380 015

रद्दीकरण संबंधी सूचना Cancellation Notice

दिनांक 06.08.2016 के विज्ञापन सं.सैक-डेकू :02:2016 के पद कोड-04 के द्वारा अधिसूचित वैज्ञानिक/अभियंता-एससी (कंप्यूटर साइंस) की 13 रिक्तियों के लिए भर्ती को रद्द किया जाता है।
13 vacancies for recruitment to the post of Scientist/Engineer-SC (Computer Science) notified vide Post Code – 04 of Advt. No. SAC-DECU:02:2016 dated 06.08.2016 stands cancelled.

हस्ता. Sd/-
प्रधान, का. एवं सा.प्र. Head, P & GA

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED
(श्रेणी–क, मिनी रत्न, सरकारी उपक्रम)
(SCHEDULE-A, Mini Ratna, Government PSU)

CW SYSTEM EQUIPMENT PACKAGE
FOR KHURJA SUPER THERMAL POWER PROJECT (2x660 MW) LOCATED AT VILLAGE DUSHAHARA, TEHSIL KHURJA, DISTT. BULANDSHEHAR, STATE OF UTTAR PRADESH
INVITATION FOR BIDS (IFB)/NOTICE INVITING TENDERS (NIT)
(Domestic Competitive Bidding)

IFB Number : 2021_THDC_631630 **Date : 29/05/2021**
Bidding Document no (if any) : THDC/RKSH/CC-9915-412 **Name of Package/Work:** CW System Equipment Package, **Type of Bidding:** E-tendering / Single Stage Two Envelope, **Bidding Document Download :** From 29-05-2021 to 06-07-2021 upto 1500 hrs (IST), **Receipt of Techno-Commercial and Price Bids :** 06-07-2021 upto 1500 hrs (IST), **Date and Time of opening of Techno-Commercial Bids:** 07-07-2021 at 1500 hrs (IST), **Date and Time of opening of Price Bids:** Shall be intimated separately.
Contact details: GM (Corporate Contracts), **THDC INDIA LIMITED** Pragati Bhawan, By-Pass Road, Pragatipuram, Rishikesh - 249 201 **Tel:** 0135-2431461/2473229/2473407, **Email:** corpcontract@thdc.co.in **Website:** https://www.eprocure.gov.in or www.thdc.co.in
Registered Office: Bhagirathi Bhawan, (Top Terrace), Bhagirathipuram, Tehri Garhwal-249001, CIN: U45203UR1988GOI009822

EXTRACT OF THE AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH 2021

(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE					CONSOLIDATED				
		QUARTER ENDED			YEAR ENDED		QUARTER ENDED			YEAR ENDED	
		31-Mar-21 (Audited)	31-Dec-20 (Unaudited)	31-Mar-20 (Audited)	31-Mar-21 (Audited)	31-Mar-20 (Audited)	31-Mar-21 (Audited)	31-Dec-20 (Unaudited)	31-Mar-20 (Audited)	31-Mar-21 (Audited)	31-Mar-20 (Audited)
1	Revenue from operations	1,11,670.64	83,672.95	85,381.04	3,10,468.78	3,20,305.08	1,13,190.42	84,548.94	86,438.26	3,14,416.94	3,23,653.63
2	Other Income	4,399.30	4,797.18	6,850.64	19,487.87	25,803.46	3,985.05	4,880.58	6,635.34	18,877.69	25,553.60
3	Total Income	1,16,069.94	88,470.13	92,231.68	3,29,956.65	3,46,108.54	1,17,175.47	89,429.52	93,073.60	3,33,294.63	3,49,207.23
4	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	19,857.62	11,755.31	17,221.05	50,553.25	67,550.90	20,136.06	12,039.55	17,224.40	51,128.64	68,301.91
5	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4,361.14	11,755.31	17,221.05	35,056.77	67,550.90	4,639.58	12,039.55	17,224.40	35,632.16	68,301.91
6	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,054.10	8,819.87	12,972.46	25,949.73	43,024.37	3,141.08	9,031.86	12,897.68	26,145.56	43,385.96
7	Share of Profit/(Loss) in Joint Venture Entities	-	-	-	-	-	(648.28)	(224.57)	(929.10)	(1,254.60)	(1,004.08)
8	Profit for the period	3,054.10	8,819.87	12,972.46	25,949.73	43,024.37	2,492.80	8,807.29	11,968.58	24,890.96	42,381.88
9	Total comprehensive income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)]	4,118.38	8,459.64	10,846.23	25,865.54	39,966.64	3,553.45	8,452.03	9,794.40	24,817.95	39,282.42
10	Paid-up equity share capital (Face Value of ₹ 5/-)	28,102.13	31,595.58	31,595.58	28,102.13	31,595.58	28,102.13	31,595.58	31,595.58	28,102.13	31,595.58
11	Other Equity				1,41,998.73	2,02,950.16				1,46,968.63	2,09,006.31
12	Earning Per Share (EPS) (₹ per share of ₹ 5/- each)										
	i) Basic & diluted EPS before Extraordinary items in ₹	0.54	1.39	2.05	4.16	6.81	0.45	1.39	1.90	3.99	6.71
	ii) Basic & diluted EPS after Extraordinary items in ₹	0.54	1.39	2.05	4.16	6.81	0.45	1.39	1.90	3.99	6.71

NOTES:
1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 8th June, 2021.
2. The Audited Accounts are subject to review by the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6) of the Companies Act, 2013.
3. These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment rules thereafter.
4. The Board of Directors have recommended a final dividend of ₹ 0.60 per share (Face value ₹ 5.00 per share) in addition to interim dividend of ₹ 1.40 per share (Face Value ₹ 5.00 per Share) paid during the year. The final dividend is subject to approval of shareholders in the Annual General Meeting.
5. Previous period figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to make them comparable to the figures of the current periods.
6. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the Stock Exchange Websites: www.bseindia.com and www.nseindia.com. The same is also available on the Company Website: www.engineersindia.com.

Place: New Delhi
Dated: 08th June, 2021

By Order of the Board
For Engineers India Limited
Sd/-
(Sunil Bhatia)
Director (Finance)
DIN: 08259936

ENGINEERS INDIA LIMITED
(A Govt. of India Undertaking)
Delivering Excellence through People

Regd. Office: Engineers India Bhavan, 1, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066; Tel.: 011- 26762121 | **E-mail:** eil.mktg@eil.co.in
Website: www.engineersindia.com | **CIN:** L74899DL1965GOI004352

Follow us :
/EngineersIND @EngineersIND
/company/engineers-india-limited